इकतारा बोले

डॉ टी महादेव राव
विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)
9394290204

क्या सही क्या गलत ?

निशुल्क या मुफ्त देना उचित है या अनुचित? इतना अजीब सा सवाल तुम्हारे मन में कैसे आया? जनता को मुफ्त बांटने पर अब तर्क-वितर्क होने लगे हैं।

बांटने दो! क्या जाता है? सारा कुछ मुफ्त बांटते जाएँ तो इसका कहीं भी तो अंत होगा न?

बांटा जाने वाला सारा नेताओं का धन और पार्टी फंड ही तो है। इससे किसी का क्या नुकसान होगा? जनता का ही नुकसान है। पार्टी फंड, प्रत्याशियों के अपने पैसों को चुनाव में टॉफियों जैसे बांटकर थोक में वोट हासिल करना पुरानी बात हो गई है। अब तो जनता का पैसा ही, जनता को बांटने वाला पुनर्चक्रीय प्रक्रिया वही रीसाइक्लिंग टेक्निक शुरू हो गई है।

यह तो नई बात लगती है। इस नैतिकविहीनता पर न तो आरोप लगाया जा सकता है और न मामला बनाया जा सकता है। यह ऐसी घपलेबाजी है। अब जनता के पास बचा ही क्या, जिसे वे नेता लोग हासिल कर पाएंगे?

बहुत हैं। कर हैं, शुल्क हैं, चीजों की कीमतें हैं, खरीद-फरोख्त हैं, दंड हैं, जीएसटी हैं। सारे में बस निचोड़ लेना ही है।

माना कि निचोड़ लिए, लेकिन फिर बांट देंगे। इसमें उनका फायदा क्या होगा?

जनता को तकलीफ न हो, इस तरीके से गुप्त आक्रमण से करों, शुल्कों, महंगाई के नाम पर भरपूर निचोड़ लेना और फिर उसे ही दान वीर कर्ण की भांति अपने हाथों से भरपूर बांटना। इस बांटने में अपनी साख, पार्टी के रंग, नेताओं की विशाल हृदयता और ख्याति अपनी जेब में भर लेना।

गरीबों को चावल दे रहे हैं न। सौ का नोट छुड़ाए बिना चूल्हे पर न आ पाती हैं दाल, तेल। माहगे दामों ज्यादा बिना न आने वाले गैस सिलेंडर के बिना राशन का चावल भी तो नहीं पकेगा। सौ सौ के नोटों के बिना कैसे आएंगी थैली में सब्जियां? बाजार आते जाते स्कूटर के लिए पेट्रोल कैसे आयेगा? यह तो कीमतों का आक्रमण है। घर में टीवी और सिनेमा दोनों का भार बढ़ गया है। आसमान छूते बस किराए और बिजली के दाम। सस्ते में आदत डलवा कर अब महंगे होते जा रहे सेलफोन के प्रभार। घर बार बर्बाद करने पर आमदा निजी अस्पतालों की फीस। बीमारी छोटी भी हुई तो हजारों का फटका और थोड़ी बड़ी बीमारी हुई तो लाखों का झटका। इस पर जनता महंगाई में यह तक सोचने लगी है कि जान रहे या न रहे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे जीने से तो.....इस तरह जनता पर जबरदस्त झटके वाली महंगाई की मार है।

स्कूल में भोजन और पढ़ाई तो मुफ्त ही है न? नाम के लिए है मुफ्त भोजन योजना। अच्छा भोजन जिससे शक्ति और पोषक तत्व मिलते हैं कहां है? बस औपचारिक भोजन और गुणवत्तारहित पढ़ाई। आ रही पीढ़ी अभी से मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हुई जा रही है। बस स्किॉर्ड्स में भरने के लिए भोजन और निशुल्क पढ़ाई हैं सिर्फ कहने मात्र के लिए। क्या इससे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? जनता को कोई विशेष फायदा मिल रहा है?

छात्रों को आगे बढ़ाने छात्रवृत्ति भी तो दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है? सरकार राशि जारी नहीं करती महाविद्यालय तो निचोड़ कर शुल्क वसूलते हैं। शुल्क बिना कक्षाओं में जाने से वंचित, पढ़ाई न कर पाने की हालत हो गई है। ऐसे में मस्तिष्क में न आती और केवल उपाधियों में दिखती पढ़ाई से न कोई रोजगार मिलता है और न कोई स्वरोजगार कर पाते हैं। बेरोजगारों की संख्या में इजाफा के अलावा कोई फायदा नहीं।

किसानों का कल्याण ही तो नेताओं का लक्ष्य है। किसानों को मदद की बात करते हैं उसके जेब में कुछ पैसे डाल कर। बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां पहुंच से बाहर के दरों में कैसे लें। मिलावट, तौल, धोखाधड़ी, बाजार में माल बेच पाना ये सारी अतिरिक्त आपदाएं हैं। अंत में अन्नदाताओं की आत्महत्याएं। क्या यही कृषकों का कल्याण है?

वृद्धों, दिव्यांगों, महिलाओं को पेंशन बांट रहे हैं न? बढ़ती कीमतों के आगे पेंशन कितना फायदेमंद है? बोलो! दिव्यांगों और महिलाओं को कोई रोजगार उपलब्ध कराए बिना, वृद्धों का उचित इलाज कराए बिना सिर्फ पेंशन बांटने से हो जाएगा कल्याण?

मुफ्त बांटने वाले नेताओं को मिलने वाला फायदा वोट ही तो है। उससे अधिक क्या होगा? जनता से करों और शुल्कों के रूप में पैसा वसूल कर, मुफ्त में बांटकर वोट, सीट और पद पाते हैं। यह सब बाहरी दिखावा मात्र है। अधिकार देने वाली सत्ता, पद देने वाली सत्ता सड़कें, परियोजनाएं, भवन, ठेकेदारी, पूंजी, उद्योग लाकर आपके हाथ पर धर देती है। गुप्त रूप से रचे कूटनीति से गुपचुप कमीशन तो अतिरिक्त आय है। यह सब पाना है तो कुर्सी हासिल करना होगा। इसलिए निशुल्क का नाटक और मुफ्त का मजमा लगाना होगा। उसके लिए फिर जनता को ही निचोडना होगा। यह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चक्रीय स्थिति है। सभी खिलाड़ी हैं। सिर्फ सामान्य जन ही यज्ञ की समिधाएं हैं, जो जलकर सोना देते हैं इन नेताओं को।

अगर जनता से जबरदस्ती निचोड़ा जा रहा है तो क्या जनता को पता नहीं चल रहा? मतदाता या वोटर पैदा होते ही किसी न किसी निशुल्क या मुफ्त योजना का लाभ लेने वाला लाभार्थी होता है। जैसे-जैसे बढ़ता है अतिरिक्त निशुल्क योजनाएं उसके साथ जुड़ती जाती हैं। अंत में उसकी मौत भी निशुल्क योजना में होती है। इस तरह पैसे दो पैसे वाली योजनाओं में ही जनता खुश है, लेकिन सरकारी महोदय सारे अपनी बड़ी-बड़ी तिजोरियां भर, भोजन करते रहते हैं। यह सब थप्पड़ मार कर मरहम लगाने वाली बात है। पेट पीठ एक कर भूखों मरने के बाद भी पता नहीं जनता कब चेतेगी? कब उसके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और यथार्थ को जान पाएगी? उस दिन की प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहे हैं हम सब।

मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद...

भोजशाला विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भूचाल

भोपाल/धार (इं)। भोजशाला विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट ने नया भूचाल ला दिया है। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के आदेश के पालन में एएसआई ने 22 मार्च 2024 से भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर और उसके 50 मीटर परिधीय क्षेत्र में वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन किया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की गई और इस दौरान मौजूदा संरचना के स्वरूप को बदले बिना काम किया गया। जांच और उत्खनन के दौरान मिली सभी वस्तुओं का विधिवत दस्तावेजीकरण किया गया। इनमें शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, पत्थर, धातु और कांच की वस्तुएं शामिल हैं। जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि भोजशाला में मंदिर और मठ था। इन्हें मुगल काल में ध्वस्त करके वहां स्थापित मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इसकी गवाही परिसर में बनाई गई अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के गेट पर लगा एक शिलालेख दे रहा है। यह शिलालेख 1436-1469 ई. तक मालवा सल्तनत के सुल्तान रहे खिलजी वंश के संस्थापक महमूद खिलजी का है। इस शिलालेख का उल्लेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में खंड चार के पृष्ठ संख्या 260 पर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस शिलालेख की 17वीं और 18वीं पंक्तियों में लिखा है कि यहां पहले एक प्राचीन धार्मिक मंदिर और शैक्षणिक केंद्र (मठ) मौजूद था। उस स्थल पर देवताओं की मूर्तियां थीं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और इस स्थान को मस्जिद व मजार में परिवर्तित कर दिया गया।

जांच में सामने आए चौकाने वाले तथ्य

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक सर्वेक्षण, उत्खनन, शिलालेखों के अध्ययन, मूर्तियों और स्थापत्य टुकड़ों की जांच के आधार पर कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना एक पूर्ववर्ती बेसाल्ट संरचना के ऊपर निर्मित है जिसका निचला हिस्सा आज भी आधार के रूप में मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्थल पर वास्तुकला के तीन अलग-अलग चरण रहे। मौजूदा ढांचा तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले के क्षतिग्रस्त ढांचे के ऊपर निर्मित है। उत्खनन में पक्की ईंटों से बनी संरचनाएं भी मिलीं। दक्षिण-पश्चिम कोने में खुदाई के दौरान सामने आई दीवारें बताती हैं कि शुरुआती संरचनाएं प्राकृतिक मिट्टी पर ईंटों से बनी थीं। मोटी और ऊंची दीवारें संकेत देती हैं कि यह संभवत: सार्वजनिक उपयोग की विशाल संरचना रही होगी। मुख्य संरचना के आसपास की संरचनाओं का स्तर समय-समय पर ऊंचा किया गया, जिससे संकेत मिलता है कि यह स्थल लंबे समय तक उपयोग में रहा। ठोस चबूतरे, मोटी ईंटों की दीवारें और फर्श सार्वजनिक उपयोग का संकेत देते हैं।

साल 1951 में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम के तहत भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। इसी वजह से पूरी जांच बेहद सावधानी से की गई ताकि मौजूदा ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वे आंगन में किया गया। इसमें तीन परतों वाली भू-आकृति का पता चला। पहली परत लगभग 1 मीटर मोटी है, जिसमें पत्थर की पट्टियों से बनी संरचनाएं हैं और स्पष्ट स्तरीकरण नहीं दिखता। दूसरी परत 4-5 मीटर तक फैली है और खंडित सामग्री से भरी है। तीसरी परत 5 मीटर से अधिक गहराई में है और इसे लगभग अक्षुण्ण आधार स्तर माना गया है, जहां सभी संरचनाएं स्थित हैं।

दोनों पक्ष के अपने-अपने दावे- मामले में याचिकाकर्ता (मंदिर पक्ष) आशीष गोयल का कहना है कि शिलालेख इस बात की गवाही देता है कि यहां प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर मूर्तियों को नष्ट किया गया और बाद में मस्जिद में परिवर्तित किया गया। सर्वे का यह तथ्य भोजशाला को सरस्वती (वाग्देवी) मंदिर सिद्ध करने के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। वहीं, कमाल मौलाना वेलफेयर कमेटी, धार के सदर अब्दुल समद (मस्जिद पक्ष) का तर्क है कि 1903 और 1904 में एएसआई के ही सर्वे में यह स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि यह स्थान मस्जिद है और उसकी संरचना भी मस्जिद जैसी ही है। अब नई सर्वे रिपोर्ट में तथ्य बदले नजर आ रहे हैं। हम कोर्ट में आपत्तियां दर्ज कराएंगे। इस बीच, लंदन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी (सरस्वती) की मूर्ति को भारत वापस लाने का मुद्दा गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में उठा। गौरतलब है कि वाग्देवी की प्रतिमा 1930 में अंग्रेज अपने साथ ले गए थे और यह प्रतिमा फिलहाल लंदन के म्यूजियम में रखी है। भोजशाला के सरस्वती (वाग्देवी) मंदिर बनाम मौला कमाल दरगाह मस्जिद विवाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन है। 2024 में एएसआई द्वारा 98 दिन तक किए गए भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की 2189 पृष्ठों की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद पक्ष से आपत्तियां मांगी हैं। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को प्रस्तावित है।

जगह-जगह मंदिर होने के मिले प्रमाण

एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट में शिलालेख पर फारसी में मुद्रित बातों का पक्षकारों की सुविधा के लिए अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया है। उसके अनुसार, खिलजी शासक महमूद शाह के शिलालेख की आयत 17-18, जो हिजरी वर्ष 859 (1455 ईस्वी) का है इसमें लिखा है- एक बहादुर व्यक्ति बड़ी सेना के साथ धर्म के केंद्र से इस पुराने आश्रम (मठ) में पहुंचा। उसने देवताओं की मूर्तियां तहस-नहस कर दीं और पूजने की जगह (मूर्तियों-मंदिर) को ताकत के बल पर नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद बना दिया। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, शिलालेख की लिखावट, परिसर में मिली मूर्तियों और वास्तुकला के अवशेष बताते हैं कि पत्थर की मूल संरचना को बाद में बदलकर मस्जिद बनाया गया। खंभों और स्तंभखंड की कला से संकेत मिलता है कि ये पहले मंदिर का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में मस्जिद निर्माण में पुनः उपयोग किया गया। खिड़की फ्रेम पर देवी-देवताओं की मूर्तियां अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। एक खंभे पर देवताओं की कटी-फटी आकृतियां हैं। भोजशाला का सच यही है कि इसके रूप को बदला गया। मंदिर को मस्जिद में बदलने के लिए इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। यह कहना है सेवानिवृत अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, धार, डीके रिछारिया का।

रेलवे द्वारा बनाए 107 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ओवर ब्रिजों का केंद्रीय मंत्री ने किया लोकार्पण

धार से ज्ञानेंद्र त्रिपाठी। धार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन परियोजना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सागौर एवं मानपुर स्थित ब्रिज क्रमांक 234 ए एवं 221 ए के दो रेलवे ओवर ब्रिजों का लोकार्पण केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा जनता की सेवा में समर्पित किया गया। लगभग 107 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इन दोनों ओवर ब्रिजों का निर्माण कार्य पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने किया है।

केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि ये ओवर ब्रिज क्षेत्र की जनता को सुरक्षित, सुगम एवं निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान करेंगे। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की यह मांग थी, जो आज पूर्ण हुई है। उन्होंने बताया कि कुछ दिवस पूर्व ही उन्होंने इंदौर-दाहोद नई रेल लाइन के प्रगतिरत कार्यों का विशेष ट्रॉली में बैठकर विस्तृत निरीक्षण किया था तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि निर्माण कार्य समय-सीमा में एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। आज इन ओवर ब्रिजों का लोकार्पण उसी प्रतिबद्धता का परिणाम है।केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने उपस्थित जनसमुदाय को विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को रेलवे परिवहन की सीधी सुविधा मिलने जा रही है। रेल संपर्क प्रारंभ होने से आदिवासी अंचल में व्यापार, शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सेवाओं के नए अवसर विकसित होंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट संकल्प है कि आदिवासी अंचलों में विकास कार्य सर्वांगीण रूप से निरंतर चलते रहें। सड़क, रेल, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। केंद्र सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सागौर एवं मानपुर के ये ओवर ब्रिज केवल यातायात की सुविधा नहीं, बल्कि क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक हैं। आने वाले समय में लोकसभा क्षेत्र में और भी विकास कार्यों को गति दी जाएगी, जिससे क्षेत्र समग्र प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। कार्यक्रम में धार भाजपा जिला अध्यक्ष निलेश भारती, रेलवे डीआरएम श्री अश्विनी कुमार जी सहित समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, आमजन एवं कार्यकर्ता बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

जनपद मनासा में आजीविका होली मेले का हुआ आयोजन

मनासा। 27 फरवरी शुक्रवार को जिला पंचायत नीमच के तत्वाधान में आजीविका मिशन मनासा के अंतर्गत आजीविका होली मेले का आयोजन किया गया।

जनपद पंचायत मनासा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह की दीदीयो द्वारा अपनी अपनी गतिविधियों की दुकानें लगाई गई, प्रदर्शनी मेला एवं होली मिलन समारोह का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने द्वारा निर्मित उत्पादों की 17 दुकानें लगाई गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणजन पहुंचे। मेले में हस्तनिर्मित वस्त्र, मसाले, पापड़, अचार, अगरबत्ती, सजावटी सामग्री , दूध से निर्मित मावा, मिठाई, घी एवं घरेलू उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्रदर्शित किए गए। होली मिलन समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, गीत-संगीत एवं रंग-गुलाल के साथ आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं मिशन से जुड़ी समूह की सदस्याएं उपस्थित रहीं। अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दीदीयो ने अपनी अपनी सफलता की कहानी सुनाई गई महिलाओं को स्वरोजगार के लिए निरंतर प्रयासरत रहने हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास और उत्साह का संचार किया। जन प्रतिनिधि ने मेले की शुभारभ रिबन काटकर, मां सरस्वती जी पूजा करते हुए की , जन प्रतिनिधि में जिला पंचायत उपाध्यक्ष शंभुलाल धाकड़, विधायक प्रतिनिधि के रूप में कैलाश पुरोहित मंडल अध्यक्ष,यशवंत बंजारा, श्याम लाल वसीटा जिला पंचायत प्रतिनिधि, मंगीलाल जिला पंचायत सदस्य साथ ही आजीविका मिशन से नीमच से हेमंत रामावत डीएम कृषि , प्रकाश पालिया एडीएम, ब्लॉक से नरेंद्र परमार ब्लॉक मैनेजर, दीपक डावर, कमल भूरिया, महेंद्र अलावा, जितेन्द्र यादव उपस्थित रहे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में आईटीआई संस्थान विकास समिति की वार्षिक बैठक

धार। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में आई.टी.आई. संस्थान विकास समिति की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संस्थान के वार्षिक आय-व्यय विवरण, वर्तमान शैक्षणिक गतिविधियों तथा आगामी सत्र की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। आई.टी.आई. धार में चरणबद्ध रूप से नए ट्रेड प्रारंभ करने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तथा आवश्यक संसाधन एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लिए गए। बैठक में आई.टी.आई. प्लेसमेंट की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने, संस्थान विकास निधि से संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करने, कार्यशालाओं हेतु कक्षाओं की मरम्मत एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर सहमति व्यक्त की गई। इस दौरान एन.एल.एम. (नवीन लर्निंग मैटेरियल) अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 की पुस्तकों के मुद्रण, भंडारण एवं वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने संस्थान को और अधिक प्रभावी एवं रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने पर बल दिया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक चौधरी, अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पांडेय, जिला पंचायत की अध्यक्ष तथा समिति के सदस्य एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

धार। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए कि जिले में इस वर्ष नवीन रूप से चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट्स का तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा भौतिक निरीक्षण कर अविलंब आवश्यक सुधारात्मक कार्य सुनिश्चित किए जाएँ। साथ ही जिले में संचालित जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागीय समन्वय के साथ ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा जिले से गुजरने वाले फोरलेन मार्गों पर अवैध मीडियन कट को बंद करने के लिए सख्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम राहत (कैशलेस) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में परिवहन एवं पुलिस विभाग को संपूर्ण जिले में प्रवर्तन से संबंधित विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

लंगूर के पंच-सरपंच और ग्रामीणों ने किया धरना-प्रदर्शन

मनावर (इंदौर समाचार)। ग्राम पंचायत लंगूर के पच सरपंच और ग्रामीण जनों के द्वारा आज पंचायत कार्यालय मनावर पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मनावर को दिया गया। धरने का मुख्य कारण ग्राम पंचायत लंगूर में पिछले वर्ष नवीन पंचायत भवन की 37,50 रुपए की मंजूरी नेशपुरा में अस्पताल के पास बनाने की मंजूरी प्राप्त हुई थी जिसका ठहराव प्रस्ताव पंचायत ओर ग्राम सभा में भी सर्व सम्मति से पास हुआ था इसके बावजूद जनपद पंचायत सी, ओ, अंकिता अलावाजी राजनीतिक दबाव में उस स्थान पर उप यंत्री को ले आउट नहीं डलवा रही है जिससे सभी ग्राम पंचायत लंगूर के पंच सरपंच और ग्रामीण जनों ने साथ ही सभी मनावर कांग्रेस जनों ने धरने प्रदर्शन में भाग लेकर जनपद पंचायत सी, ओ अंकिता अलावाजी के खिलाफ कारवाही की मांग का एक ज्ञापन भी सौंपा उक्त जानकारी नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ओम सोलंकी मनावर द्वारा दी गई।

बाबूजी प्रीमियर लीग 2.0 10 मार्च से, 140 से अधिक टीमें होंगी शामिल

बदनावर। (इंदौर समाचार)। विधायक भंवरसिंह शेखावत के मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र में क्रिकेट खिलाडियों एवं खेल प्रेमियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता बाबूजी प्रीमियर लीग 2.0 का आयोजन 10 मार्च से होगा। प्रतियोगिता में शामिल क्रिकेट टीमों को 4 ग्रुप में शामिल किया गया। क्रिकेट टीम कप्तानों की मौजूदगी में नियमानुसार 4 ग्रुप में शामिल कर लाटस डाले गए। बाबूजी प्रीमियर लीग 2.0 में 140 से अधिक टीमें शामिल होगी।

विधायक कार्यालय बदनावर पर बाबूजी प्रीमियर लीग 2,0 हेतु बदनावर विधानसभा की 140 से अधिक टीमे भाग लेगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण लाटस की गतिविधि ब्लॉक अध्यक्ष निरंजनं सिह पंवार, कार्यक्रम संयोजक संदीपसिंह शेखावत, विधायक प्रतिनिधि महेश पाटीदार, नीतिन सांखला, देवपालसिंह जादव, नरेन्द्रसिंह चोहान, दिलीप परमार, अनुप जैन, संदीप चंद्रावत एवं टीमों के कप्तान की मौजूदगी मे संपंन की गई। निरंजनसिंह पंवार, संदीपं सिह शेखावत, नितीन सांखला, महेश पाटीदार एवं नरेन्द्रसिंह चौहान ने क्रिकेट टुर्नामेंट संबधी नियम व दी जाने वाली सुविधाओ के बारे में बताया गया। टेनिस बाल प्रतियोगिता में टीम के सभी खिलाडियों को केमिटी की और दी गई टी शर्ट पहनना अनिवार्य है। साथ ही मेच खेलने वाली टीम को निर्धारित समय पर नही पहुँचने पर सामने वाली टीम को वाकर दिया जाएगा। प्रत्येक मेच 8 ओवर का होगा। विधानसभा के बाहर का खिलाडी पूर्णत प्रतिबंधीत रहेगा। लाटस डालने के दौरान नागदा, बदनावर, पंचकवासा, घटगारा, नौगावा, बाबरडा, कानवन, संदला, मुलथान, खेडा, काछ्रबडोदा, कंकराज, तिलगारा, कोद, बिडवाल, कडोदकला, शेरगढ, सिलौदा, बाबरडा, पलवाडा, माकनी, ढोलानाकला, कोद सहीत कई गांवों की टीम के कप्तान मौजूद थे। बाबूजी प्रीमियर लीग 2.0 के प्रति क्षेत्र में काफी उत्साह का माहोल है। पिछली प्रतियोगिता में करीब 100 टीमों ने सहभागिता की थी। प्रतियोगिता के सभी मेच का सीधा प्रसारण मोबाइल व टीवी पर दिखाया गया था। अंपायर के निर्णय पर रिव्यु लेने की भी सुविधा मिली थी।बाबूजी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रति गांवों में काफी जोश व जुनुन देखा गया है।